कृषि सम्मेलन एवं बजट पूर्व कार्यशाला के दौरान उभरी कृषि से संबंधित मांगे एवं अपेक्षाएं

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र (बार्क) द्वारा दिनांक **21 नवम्बर 2012 को राज्य स्तरीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें राज्य की ड्राफ्ट कृषि नीति, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जलवायु परिवर्तन तथा राज्य सरकार की जलवायु परिवर्तन की कार्ययोजना पर चर्चा की गई।**

इसके पूर्व दिनांक 5 अक्टूबर 2012 को राज्य संदर्भ केन्द्र, जयपुर में एवं 20 नवम्बर 2012 को विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर में राज्य की स्वंय सेवी संस्थाओं के साथ बजट पूर्व कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था जिसमें अन्य मुद्दों के साथ कृषि पर भी चर्चा की गई।

यहां बार्क के बजट पूर्व कार्यशालाओं तथा कृषि सम्मेलन में उभरे कृषि से संबंधित चिंताओं, सुझावों तथा मांगों को प्रस्तुत किया जा रहा है।

- राज्य सरकार द्वारा तैयार कृषि नीति में पंचायतों को शामिल नहीं किया गया है। अतः सरकार कृषि नीति में पंचायतों की भूमिका को स्पष्ट करे।
- राज्य में कृषि की कार्ययोजना गांव, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर अलग अलग तैयार हो तथा सरकार सरकार उसे राज्य आयोजना में शामिल करे।
- राज्य अपनी कृषि योजना एग्रो क्लाईमेटिक जोन को ध्यान में रखते हुये तैयार करे।
- राज्य सरकार समस्त कृषि उत्पादों का उचित मूल्य निर्धारित करे।
- सरकार किसानों को उनकी उपज के निर्धारित मूल्य के प्राप्त होने की गारंटी दे।
- अनावृष्टि या अतिवृष्टि की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा फसल नुकसान के मुआवजे में दी जाने वाली राशि को बढ़ाया जाये।
- सरकार निजी कंपनियों के माध्यम से बीज वितरण प्रणाली को बंद करे।
- सरकार कृषि एवं बीज वितरण से संबंधित कार्यक्रमों में वितरण की प्रणाली में सुधार करे।
- राज्य में निजी कंम्पनियों के बीज उपयोग करने की स्थिति में फसल का नुकसान होने पर निजी कंम्पनियों की जवाबदेही तय की जाये तथा मुआवजा मिलना सुनिश्चित किया जाये।
- सरकार तय करे कि बांधों (डैम) के जल का उपयोग सर्वप्रथम सिंचाई में उसके पश्चात पेयजल के किया जाये।
- सरकार राज्य में बंजर भूमि के विकास के लिये 'वेस्ट लैंड बोर्ड' का गठन करे।
- सरकार रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से राज्य में कोल्ड स्टोरेज भवनों का निर्माण करवाये।
- चारागाह विकास हेतु आवश्यक कुंआ निर्माण को नरेगा के अंतर्गत करवाया जाये।
- राज्य के खेतीहर किसानों के लिये परिवहन सेवाओं का विकास किया जाये ताकि वे अपनी उपज को सही समय पर बाजार में बेच सकें।
- सरकार पशुपालन एवं कृषि को जोड़ने के कार्यक्रम चलाये तथा पशुपालन को आजीविका कमाने के साधन के रूप में विकसित करे।
- सरकार क्लाईमेट एक्शन प्लान का क्रियान्वयन करने की योजना बनाये तथा कृषि से इसका जुड़ाव बढ़ाने पर ध्यान दिया जाये।
- सरकार क्लाईमेट एक्शन प्लान के संबंध में आमजन के लिये जागरूकता कार्यक्रम चलाये।
- सरकार उर्जा संरक्षण हेतु जागरूकता फैलाये तथा उर्जा के अन्य स्रोतों जैसे–सौलर एवं पवन उर्जा के विकास के कार्यक्रम चलाये।

- सरकार राज्य में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने पर जोर दे।
- सरकार आर.के.वी.के. एवं आईसोपोम जैसे कार्यक्रमों तक आम किसान की पहुंच बनाने का प्रयास करे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाहों की भूमि पर चारदीवारी की व्यवस्था की जाए तथा चारागाह पर अतिक्रमण से संबंधित कानूनों को सख्त किया जाये।
- सरकार कृषि नीति में महिला कृषकों एवं कृषि मजदूरों की भागीदारी के लिये उचित प्रावधान रखे।
- सरकार महिलाओं के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिये उचित प्रावधान बनाये।